जीएम सरसों को मंजूरी से भारतीय कृषि में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होगा

डॉ. शिवेंद्र बजाज एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर, फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एवं अलायंस फॉर एग्री इनोवेशन ने कहा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेजल कमिटी (जीईएसी) द्वारा जीएम सरसों को बहुत दिनों से लंबित अनुमति मिलने से भारत को दो अच्छी खबरें मिली हैं। पहला, सरसों की अनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म से देश में उत्पादन बढ़ाकर खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिलेगी। तो दूसरी ओर, इससे जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित अन्य फसलों को मंजूरी दिलाने में मदद मिलेगी। इससे हमें खाद्य सुरक्षा और पोषण की सुरक्षा हासिल करने में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

जीईएसी के इस ऐतिहासिक निर्णय द्वारा पहली बार एक खाद्य फसल के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति मिली है। डॉ. शिवेंद्र बजाज, एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर, फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एवं अलायंस फॉर एग्री इनोवेशनके अनुसार अभी तक भारत में अखाद्य बीटी कपास की फसल के ही वाणिज्यिक उत्पादन की अनुमति थी। जीएम सरसों की किस्म, धारा मस्टर्ड हाईब्रिड (डीएमएच)-11 को पूरी तरह से अप्रमाणिक और अवैज्ञानिक आधारों पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। चूंकि जीएम सरसों को जीईएसी की तकनीकी निकाय से मंजूरी मिली है, जिससे साबित होता है कि यह खाद्य तेल मानवों द्वारा उपयोग किए जाने और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। भारत सरकार भी जीएम सरसों के वाणिज्यिक उपयोग को लेकर काफी आशान्वित है। इसलिए नए और उच्च पैदावार वाले जीएम सरसों हाईब्रिड और बीजों को जल्द ही हरी झंडी मिलने की उम्मीद है।

जीएम सरसों खेल परिवर्तक बनने वाला है। यह ज्यादा पैदावार, पानी और उर्वरक के प्रभावशाली उपयोग, तेल की बेहतर गुणवत्ता और बीमारी की प्रतिरक्षा वाले हाईब्रिड का विकास करने का अवसर देता है। भारत में घरेलू तेल का उपयोग 1990 के बाद 2.5 गुना से 3 गुना बढ़ चुका है, जबकि इसके उत्पादन में मामूली बढ़त हुई है। इस वजह से हम घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अधिकांशत: आयात पर निर्भर हैं। 2020-21 में हमने लगभग 13.35 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया। डॉ. शिवेंद्र बजाज, एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर, फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एवं अलायंस फॉर एग्री इनोवेशनके अनुसार सरसों का तेल भारत में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला खाद्य तेल है। सरसों की औसत पैदावार 1,000 से 1,300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की है, जो ऑस्ट्रेलिया, चीन, और कैनेडा जैसे देशों के मुकाबले बहुत कम है।